# राष्ट्रीय शिक्षा नीति और डिजिटल शिक्षा

**रश्मि संत**
असि0 प्रो0, इतिहास
डॉ0 आम्बेडकर रा0 स्ना0 महाविद्यालय ऊँचाहार, रायबरेली

***शोध–सार***

*किसी भी देश के विकास और प्रगति के लिए शिक्षा एक मूलभूत तत्व होता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति का, व्यक्ति से समाज का और समाज से देश का भविष्य संवारा जा सकता है। अतः बदलती परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा नीति का होना अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए 21वीं सदी में एक ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस होने लगी जिसके द्वारा व्यक्ति ने केवल साक्षर हो बल्कि अपनी रचनात्मक क्षमताओं को विकसित कर सके, तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ सके, आजीविका के बेहतर विकल्प ढूँढ सके, नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी सामाजिक और धार्मिक सोच विकसित कर सके। इन्हीं मौलिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ0 रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने 29 जुलाई को नयी शिक्षा नीति को प्रस्ताव पेश किया। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए नई शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया है और इस दिशा में आनलाईन शिक्षा के लिए कई प्रकार के प्लेटफार्म तैयार किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक छात्र–छात्राएं इण्टरनेट के माध्यम से ई–कण्टेण्ट का उपयोग कर शिक्षा हासिल कर सकें। इस तरह डिजिटल शिक्षा का उद्देश्य आनलाईन गुणवत्तापरक शिक्षा का विकास करना है।*

***मुख्य बिन्दुः*** *शिक्षा, डिजिटल, ऑनलाईन , ई–कन्टेंट, इंटरनेट, प्लेटफॉर्म, नीति।*

पूर्व इसरों प्रमुख के0 कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की गठित समिति ने नयी शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। 1986 की शिक्षा नीति (1992 में इसमें कुछ संशोधन हुए) के बाद 34 साल बाद आयी नयी शिक्ष नीति के अन्तर्गत कई बड़े बदलाव किये गये–

1. कक्षा पाँच तक मातृभाषा में पढ़ाई।
2. साल 2030 तक 100% जीईआर (Grass enrolment Ratio) का लक्ष्य
3. 10+2 के ढाँचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम लागू होगा।
4. बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर जोर।
5. NCERT द्वारा 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ''प्रारम्भिक बचपन देखभाल और शिक्षा'' की पहल।
6. शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक 2022 तक विकसित करना।
7. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है यानि डा0 रमेश पोखरियाल देश के पहले शिक्षा मंत्री हो गये है।
8. GDPका 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य। (वर्तमान में 4.43)।
9. छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू।
10. सम्पूर्ण उच्च शिक्षा निकाय के लिए भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन।

HECIके कार्यो के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय–

1. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद
2. सामान्य शिक्षा परिषद
3. राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद
4. उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद

11. उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 फीसदी GER (Grass Enrollment Ratio) पहुँचाने का लक्ष्य (वर्तमान –26.3)
12. पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू। अर्थात कई स्तर पर पाठ्यक्र छोड़ने के अनुसार डिग्री या प्रमाण पत्र।

4 वर्ष शोध के साथ स्नातक
3 वर्ष स्नातक डिग्री
2 वर्ष एडवांस डिप्लोमा
1 वर्ष प्रमाण पत्र

13. विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अंको को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' की स्थापना और इसी आधार पर डिग्री प्रदान।
14. एम0फिल कार्यक्रम की समाप्ति।
15. देश में आई आई टी और आई आई एम के समकक्ष 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Research Universities – MERU)की स्थापना।

2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डिजिटल प्लेटफार्म की बात कही गयी है। इसके तहत मोबाइल एप, डिजिटल शिक्षा, मूल्यांकन में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। वर्ष 2020 में जिस तरह से कोविड–19 का संकट हावी रहा उसके कारण सम्पूर्ण समाज वर्चुअल एवं डिजिटल पद्धति में कूद पड़ा है। ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट बोर्ड कम्प्यूटर एवं अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा छात्रों में सीखने की प्रवृत्ति में सुधार किया जा सकता है। इसलिए नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा का महत्व समझा गया। साथ ही इन वैकल्पिक साधनों के इस्तेमाल से शिक्षा की गुणवत्त को बनाये रखा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को प्रशिक्षण दिया जाये।

डिजिटल शिक्षा का तात्पर्य प्रौद्योगिकी, उपकरण, अंतरक्रियाशीलता, अवधि, अध्ययन सामग्री और उपयुक्त प्लेटफार्मो के माध्यम से कक्षा में शिक्षण को और अधिक संवादात्मक बनाना है। मगर इस दिशा में आ रही कठिनाइयों का कारण डिजिटल शिक्षा, अवसंरचनात्मक ढाँचे, अध्ययन सामग्री, सहभागिता और कई भाषाओं में उपलब्ध एक उचित नीति का अभाव है।डिजिटल शिक्षा प्रणाली में बहुत सी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। यूँ तो शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी फोरमबनाने का प्रस्ताव है मगर शिक्षविद निधि सत्प्रत चतुर्वेदी का कहना है कि इसे चलाने के लिए पर्याप्त इंटरनेट कनेक्टविटी और कम्प्यूटर की आवश्यकता होगी।आंकड़ों के हिसाब से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा ऐसा देश है जहाँ इंटरनेट उपभोक्ता अत्यधिक है किन्तु फिर भी यहाँ की केवल 50% जनसंख्या की पहुँच ही इंटरनेट तक है। 27 प्रतिशत छात्रों के पास अपने खुद के स्मार्टफोन या लैपटॉप ऑनलाइन कक्षाओं के लिए नहीं है।अब जब हम ऑनलाइन कक्षाओं की बात करते है तो इसका मतलब है कि शिक्षकों का छात्र–छात्राओं के साथ वीडियों कॉल द्वारा संवाद या ऑनलाइन विडियों के माध्यम से व्याख्यान। इसके लिए स्थिर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है और जब इस प्रकार की स्पीड की कमी है तो ऑनलाइन शिक्षा का उद्देश्य विफल हो जाता है।दूसरे जिन बच्चों के पास खुद के स्मार्टफोन नहीं है वो पठन–पाठन के लिए दूसरे पर निर्भर है। तो ऐसे में ठीक प्रकार से पढ़ाई नहीं हो पाती है।

कोविड–19 से पहले मोबाइल बच्चों के इस्तेमाल में बाधक मान जाता रहा है। किन्तु कोविड–19 आने के बाद अभिभावकों की मजबूरन यही मोबाइल बच्चों को देना पड़ाताकि वे अपनी ऑनलाइन कक्षाएं कर सके। किन्तु मोबाइल का प्रयोग बच्चों द्वारा ठीक ढंग से ना करने पर वे पोर्न और अपराध की तरफ भी बढ़ सकते हैं। बच्चे खुद से पोर्न साइट ना भी खोले लेकिन इंटरनेट से जुड़ने के बाद विभिन्न तरह के शील–अश्लील वीडियों के नेटिफिकेशन आने लगते हैं और अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यह एक गम्भीर समस्या है।

बच्चे जब किसी संस्थान से जुड़ते है तो वहाँ सभी लिंग, वर्ग, जाति और समुदाय के लोगों के साथ शिक्षा प्राप्त करते है। जिससे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम होते हैं। इस प्रकार से शिक्षण संस्थान सामाजिक समावेश और सापेक्ष समानता

में एक अनुकरणीय भूमिका निभाते हैं। यह सीख ऑनलाइन शिक्षा में नही मिल पाती। स्कूलों में शिक्षक न केवल बच्चों को पुस्तकों से संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। एक तरह से शिक्षक और छात्र के बीच जो रिश्ता बनता है वो ऑनलाइन शिक्षण में इतना प्रभावशाली नहीं बन पाता। साथ ही शिक्षक भी ऑनलाइन शिक्षण के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें इतना तकनीकी ज्ञान नहीं है कि वे ऑनलाइन कक्षा में उतने ही प्रभावशाली तरह से पढ़ा सकें जितना महाविद्यालय में पढ़ाते हैं।

डिजिटल शिक्षा की इन कमियों के बाद भी लंबे संक्रमण काल में पूरे विश्व की भाँति हमारा देश भी डिजिटल युग की सच्चाई से परिचित हो रहा है। डिजिटल शिक्षा प्रणाली कोई नई बात नहीं। हाँ, कोविड–19 के कारण लोग इस तरह तेजी से उन्मुख हुए। पारंपरिक शिक्षा के मुकाबले डिजिटल शिक्षा प्रणाली के कुछ फायदे भी हैं। डिजिटल शिक्षा द्वारा तीव्र गति से हजारा छात्रों को जोड़ा जा सकता है जबकि पांरपरिक शिक्षा व्यवस्थाा में भवन निर्माण और अन्य सुविधाओं के इन्तजाम में वर्षों लग जाते है। डिजिटल शिक्षा में कॉलेज के पास सीटों का कोटा बढ़ाने का अवसर है। जिससे अधिक संख्या में बच्चे लाभ उठा सकते हैं।डिजिटल शिक्षा विशेष रूप से बच्चों के लिए प्रभावशाली भी है। इसके मौलिक ऑडियो–वीडियों बच्चों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते है। डिजिटल लर्निंग एक लचीला विकल्प है जो बच्चों को समय और गति के अनुसार अध्ययन करने की अनुमति देता है। शिक्षण में तकनीकी प्रवेश से यह एनीमेशन गॅमिफिकेशन और विस्तृत आडियो विजुअल प्रभावों के मिश्रण के साथ और अधिक प्रभावी एवं जल्दी समझने योग्य हो जाता है।

वर्ष 2020 की विपरीत परिस्थितियों के चलते ऑनलाइन शिक्षा ने अपनी एक उपयोगी जगह बनायी है। इसी लिहाज से नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली बच्चों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक छात्रों की पढ़ाई को लेकर नये कदम उठाने की बात कही गयी है। कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति के रचनात्मक और डिजिटल कदम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर ले जायेंगे।नई शिक्षा नीति प्रौद्योगिकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर केन्द्रित है। ऑनलाइन शिक्षा की हानियों को कम करते हुए हम कैसे इससे लाभ उठा सकते है, यही इस नीति का उद्देश्य है। यह नीति निम्नलिखित पहुलुओं की सिफारिश करती है–

1. ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन– इसके तहत छात्रों को उपकरणों की आदत, ई–कन्टेंट का पसंदीदा प्रारूप आदि विषयों का अध्यन किया जायेगा। साथ ही अद्यायन संचालित करने के लिए उपयुक्त एजेंसियों की पहचान कर निरंतर सुधार किया जायेगा।
2. शिक्षा के क्षेत्र में खुले, परस्पर, विकसित, सार्वजनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जायेगा।
3. शिक्षकों द्वारा संरचित स्वयम एवं दीक्षा जैसे मौजूदा ई–लर्निंग प्लेटफार्म का विस्तार किया जायेगा।
4. सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपॉजिटरी और प्रसाद कोर्स वर्क लर्निंग गेम्स और सिमुलेशन ऑगमेंटेड रियालिटी और वर्चुटल रियालिटी के निर्माण सहित कन्टेंट की एक डिजिटल रिजॉजिटरी विकसित की जायेगी।
5. डिजिटल की सीमितता को कम करने के लिए टेलीविजन, रेडियों जैसे जनसंचार के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण 24/7 किया जायेगा।
6. बर्चुअल लैब्स के लिए दीक्षा, स्वयम एवं स्वयंप्रभा जैसे मौजूदा ई– लर्निंग प्लेटफार्म का उपयोग किया जायेगा।
7. शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन शिक्षक किस प्रकार से गुणवत्तायुक्त ऑनलाइन सामग्री का निर्माण करें इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा।
8. ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र अथवा परख,

स्कूल बोर्ड, एनटीए और चिन्हित निकाय मूल्यांकन रूपरेखा का निर्धारण करेंगे।

9. सीखने के मिश्रित मॉडल– विभिन्न विषयों के सीखने के विभिन्न मिश्रित मॉडल तैयार किये जायेगे।
10. डिजिटल शिक्षण के लिए सामग्री, प्रौद्योगिकी और शिक्षाशास्त्र के मानक तैयार करना।

मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों के सीखने के लिए कई परियोजनएं शुरू की जैसे दीक्षा मंच, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, ऑनलाइन एम. ओ. सी. पाठ्यक्रम ऑन एयर–शिक्षा वाणी, दिव्यांगों के लिए एनआई ओ.एस. द्वारा विकसित डेली, ई–पाठशाला, ओपन एजुकेशन, रिसोर्सेज की राष्ट्रीय रिपोजिटरी, टीवी चैनल, ई–लर्निंग पोर्टल, वेबिनार, चैट समूह और पुस्तकों के वितरण की पहल की है। इसके अलावा छात्रों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया टूल जैसे– व्हाट्सएप ग्रुप, यू–ट्यूब चैनल, गूगल मीट, स्काइप और जूम द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं, ई–लर्निंग पोर्टल, टीवी, रेडियो और दीक्षा का उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा भी डिजिटल पहल की जा रही है।राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (भारत नेटवर्क) के माध्यम से सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 100 Mbps बैंडविडथ प्रदान करने की परिकल्पना करती है ताकि ऑनलाइन सेवाओं को ग्रामीण भारत के सभी लोगों तक पहुँचाया जा सके। इसी प्रकार राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक नेटवर्क जैसे TEIN4, गरूड (GARUDA) CERNऔर इंटरनेट उच्च शिक्षा और शोध के सभी संस्थानों को आपस में जोड़ना है।

ग्रामीण क्षेत्रों डिजिटल साक्षरता के लिए 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' की शुरूआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गयी हैं। इसके तहत ग्रामीणों को कम्प्यूटर व डिजिटल उपकरणों जैसे टेबलेट स्मार्टफोन आदि की ट्रेनिंग तथा ई–मेल भेजना और प्राप्त करना, इण्टरनेट द्वारा सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना, ऑनलाइन पेमेंट आदि की ट्रेनिंग दी जायेगी। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता से अनभिज्ञ परिवारों को इसका लाभ दिया जायेगा।

ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में उ0प्र0 सरकार पॉच महीनों में 45 हजार ग्राम सभाओं को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ने की योजना की ओर अग्रसर है। उ0प्र0 सरकार की ओर से डिजिटल लाइब्रेरी का कार्य भी शुरू किया गया है ताकि बच्चे पढ़ाई के लिए कंटेंट की आसानी से डाउनलोड कर सकें। डिजिटल लाइब्रेरी में राज्य विश्वविद्यालयों के लगभग 1700 शिक्षकों ने कला, वाणिज्य, विज्ञान समेत कई विषयों पर 53000 से अधिक ई–सामग्री अपलोड की है।

इस प्रकार नयी शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने ''आज की दीक्षा डिजिटल शिक्षा'' के आधार पर निर्धारित की है। डिजिटल शिक्षा वर्तमान समय की मांग भी है और आवश्यकता भी। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रख्कर जो कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है और जिस पर तेजी से कार्य भी चल रहा है। वह निःसंदेह भारत के विकास के लिए एक अच्छा कदम साबित होगा।

## संदर्भ सूची

1- hindi.careerindia.comAug-05, 2020
2- www.Jagranjosh.com, नई शिक्षा नीति 2020
3- hindi.news18.com, नई शिक्षा नीति 2020: नीति, नीयत और नियमन–प्रकाश उप्रेती
4- www.bbc.com,नई शिक्षा नीति 2020
5- www.drishtias.com,नई शिक्षा नीति 2020
6- www.jagran.com,कमल वर्मा: बदलते दौर में भारत को भी डिजिटल शिक्षा नीति की दरकार, 24 दिसम्बर, 2020
7- https://bachpanexpress.com,
8- प्रो0 प्रीती सक्सेना: नैतिक एवं डिजिटल शिक्षा द्वारा समता एवं विकास की ओर अग्रसर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
9- इंडियन एक्सप्रेस, 03 सितम्बर 2020
10- Digital India is not prepared for digital education.
11. धर्मेन्द सिंह – नई शिक्षा नीति में डिजिटल साक्षरता पर जोर, बढ़ाने होगे संसाधन, 08 अगस्त, 2020

12- www.statista.com, Sandhya Keelery- Internet usage in India, Statics and facts, July-7, 2020
13- www.hindustantimes. com
14- इंडियन एक्सप्रेस, 03 सितम्बर 2020
15- Digital India is not prepared for digital education.www.jagran.com,
16- कमल वर्माः बदलते दौर में भारत को भी डिजिटल शिक्षा नीति की दरकार, 24 दिसम्बर, 2020
17- इंडियन एक्सप्रेस, 03 सितम्बर 2020
18- Digital India is not prepared for digital education.www.amarujala.com
19. सृजन पाल सिंहः डिजिटल शिक्षा के लिए चाहिए नया निवेश, 22 अक्टूबर 2020
20. इंडियन एक्सप्रेस, 03 सितम्बर 2020
21- Digital India is not prepared for digital education.www.jagran.com
22. संजय पोखरियाल –नई शिक्षा नीतिः सुशिक्षित समाज की दिशा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर डिजिटल कदम, 02 जनवरी 2021www.education.gov.in
23. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव विकास संसाधन मंत्रालयiasexamportal.com
24. डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट– 2020
25. इंडियन एक्सप्रेस, 03 सितम्बर 2020
26- Digital India is not prepared for digital education.pmmodiyojna.in
27. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान,द्वारा अफ्शा गुल, 30 जनवरी 2021Khaskhabar. Com
**28-** पल्लव शर्मा, अब गॉव के साथ जुड़ सकेंगे उ0प्र0 सरकार की डिजिटल लाइब्रेरी